



राष्ट्रीय कृषि संहिता

प्रारंभिक परीक्षा के लिये:

[भारतीय मानक ब्यूरो](#), [राष्ट्रीय भवन संहिता](#), [राष्ट्रीय वदियुत संहिता](#), [इंटरनेट ऑफ थगिस](#), [अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन](#), अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रो-तकनीकी आयोग।

मुख्य परीक्षा के लिये:

राष्ट्रीय कृषि संहिता, कृषि में मानकीकरण, भारत में कृषि नीतियाँ, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप।

[स्रोत: IE](#)

चर्चा में क्यों?

[भारतीय मानक ब्यूरो \(BIS\)](#) संपूर्ण कृषि चक्र हेतु मानक स्थापति करने के क्रम में [राष्ट्रीय कृषि संहिता \(NAC\)](#) तैयार कर रहा है।

- भारत की [राष्ट्रीय भवन संहिता \(NBC\) 2016](#) और [भारत की राष्ट्रीय वदियुत संहिता \(NEC\) 2023](#) के आधार पर तैयार की गई इस पहल का उद्देश्य कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना तथा किसानों, नीति निर्माताओं एवं अन्य हतिधारकों के लिये स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करना है।
- NAC का मसौदा तैयार करने के साथ-साथ BIS चुनदा कृषि संस्थानों में [मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म \(SADF\)](#) स्थापति कर रहा है।

नोट: NAC को पूरा करने की संभावित समय सीमा अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है।

राष्ट्रीय कृषि संहिता (NAC) क्या है?

- उद्देश्य:** NAC का उद्देश्य खेत की तैयारी से लेकर उपज के भंडारण तक, संपूर्ण कृषि चक्र में [कृषि पद्धतियों के लिये एक मानकीकृत ढाँचा स्थापति करना है। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों को संबोधित करना है जो वर्तमान में मौजूदा मानकों द्वारा वनियमित नहीं हैं।](#)
 - वर्तमान में BIS ने [कृषि मशीनरी](#) और इनपुट के लिये मानक स्थापति किए हैं लेकिन [कृषि पद्धतियों के वनियमन में काफी अंतर बना हुआ है।](#)
- दायरा:** NAC में [फसल चयन](#), [भूमि तैयारी](#), [बुवाई](#), [सिंचाई](#), [मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन](#), [कटाई](#), [कटाई के बाद की गतिविधियाँ](#) और [भंडारण सहित सभी कृषि प्रक्रियाएँ](#) शामिल होंगी।
 - इसमें [उर्वरकों](#), [कीटनाशकों](#) और [खरपतवारनाशकों](#) जैसे इनपुट के लिये मानक भी शामिल होंगे।
 - NAC के तहत [प्राकृतिक कृषि](#), [जैविक कृषि](#) और कृषि में [इंटरनेट-ऑफ-थगिस \(IoT\)](#) प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसी आधुनिक प्रथाओं के लिये मानकों को शामिल किया जाएगा।
- संरचना:** इस संहिता को [दो भागों में विभाजित किया जाएगा:](#)
 - पहले भाग में [सभी फसलों पर लागू सामान्य सिद्धांतों की रूपरेखा](#) शामिल होगी।
 - दूसरा भाग [विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे धान, गेहूँ, तिलहन और दलहन हेतु फसल-विशिष्ट मानकों पर केंद्रित होगा।](#)
- उद्देश्य:** ऐसी राष्ट्रीय संहिता बनाना जो [कृषि-जलवायु क्षेत्रों](#), [फसल प्रकारों](#), [सामाजिक-आर्थिक विविधता](#) और [कृषि-खाद्य मूल्य शृंखला](#) के सभी पहलुओं को शामिल करती हो।
- नीति निर्माताओं और नयामकों को उनकी योजनाओं एवं वनियमों में NAC प्रावधानों को शामिल करने में मार्गदर्शन देकर [भारतीय कृषि में गुणवत्ता संस्कृति को बढ़ावा देना।](#)
 - किसानों के लिये एक व्यापक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, जिससे कृषि पद्धतियों में सूचित निर्णय लेने में सुविधा हो।
 - [समार्ट कृषि](#), स्थिरता और दस्तावेजीकरण सहित कृषि के क्षेत्रों पहलुओं को संबोधित करना।
- हतिधारकों के लिये मार्गदर्शन:** NAC किसानों, कृषि विश्वविद्यालयों और नीति निर्माताओं के लिये संदर्भ के रूप में कार्य करेगी, जिससे उन्हें

सूचित नरिणय लेने और अपने कार्यों में सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने में मदद मलिंगी ।

- **प्रशिक्षण और सहायता:** इस संहिता को अंतिम रूप दयि जाने के बाद, BIS कसिनों के लयि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने की योजना बना रहा है ताकि उन्हें मानकों को समझने एवं प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मलि सके ।

भारत में राष्ट्रीय कृषि संहिता तैयार करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **वविधि कृषि पद्धतियाँ:** भारत में जलवायु की एक वसित्तु शृंखला (15 कृषि-जलवायु क्षेत्र) के साथ मृदा के वविधि प्रकार हैं, जसिसे सभी के लयि एक ही मानक बनाना मुश्कलि हो जाता है । NAC में इन वविधिताओं को समायोजति करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है ।
- **राज्य बनाम केंद्रीय क्षेत्राधिकार:** भारतीय संवधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रवषिटि 14 के अंतर्गत कृषि, [राज्य सूची का वषिय](#) है जसिसे केंद्रीय और राज्य वनियिमों के बीच संभावति टकराव हो सकता है ।
 - राज्य के अधिकारों का सम्मान करते हुए इन कानूनों में सामंजस्य स्थापति करना प्रमुख चुनौती है ।
- **संसाधन की कमी:** कई छोटे कसिनों के पास NAC द्वारा अनुशंसति नई पद्धतियों को अपनाने के लयि संसाधनों या बुनयिदी ढाँचे की कमी हो सकती है ।
 - इसमें आधुनिक उपकरण, गुणवत्तायुक्त बीज और कुशल सचिाई प्रणालयिों तक पहुँच शामिल है ।
 - स्वीकृति सुनश्चिति करने के लयि इन समूहों को नरिमाण प्रक्रयिा में शामिल करना आवश्यक है ।
- **तकनीकी बाधाएँ:** हालाँकि इस संहिता का उद्देश्य प्रौद्योगिकिी को बढ़ावा देना है लेकनि कई कसिनों के पास आवश्यक प्रौद्योगिकिी या कौशल तक पहुँच की कमी हो सकती है । संहिता के लाभों को प्राप्त करने के लयि इन कमीयों को दूर करना आवश्यक है ।
- **डेटा और शोध अंतराल:** कृषि पद्धतयिों, पैदावार और बाज़ार के रुझानों पर व्यापक डेटा की कमी हो सकती है जो साक्ष्य-आधारति नीतिनरिमाण में बाधा डालती है । प्रभावी संहिता हेतु इन अंतरालों को संबोधति करना महत्त्वपूर्ण है ।

NAC तैयार करने में आने वाली चुनौतयिों से नपिटने के लयि क्या कयिा जा सकता है?

- **अनुकूलन और लचीलापन:** भारत भर में वविधि कृषि-जलवायु स्थतियिों को संबोधति करने के लयि NAC के भीतर क्षेत्र-वशिषिटि दशिनरिदेश वकिसति करना चाहयि ।
 - सुनश्चिति कयिा जाए कि NAC छोटे खेतों से लेकर बड़े कृषि उद्यमों तक, वभिनिन कृषि आकारों एवं संसाधन स्तरों के लयि मापनीय एवं अनुकूलनीय हो ।
- **प्र्यावरणीय वचिार:** इस संहिता के तहत कृषि वकिस को बढ़ावा देते हुए भूमि क्षरण, जल की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के समाधान पर ध्यान केंद्रति करना चाहयि ।
- **क्षमता नरिमाण:** NAC के संदर्भ में कसिनों के लयि व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम वकिसति करने चाहयि और वास्तवकि समय पर सलाह एवं सूचना साझा करने के लयि [मेघदूत जैसे मोबाइल ऐप और e-NAM तथा कसिनबंदी](#) जैसे प्लेटफॉर्म वकिसति करने चाहयि ।
- **नीतगित और वनियिमिक समर्थन:** NAC के लयि एक सहायक वधियी ढाँचा स्थापति करना चाहयि ताकि इसकी प्रवर्तनीयता सुनश्चिति हो सके और अनुपालन के लयि कसिनों को पुरसकृत करने के क्रम में **कर लाभ तथा मान्यता कार्यक्रम जैसी प्रोत्साहन संरचनाएँ** बनाई जा सकें ।

अन्य देशों में कृषि नीति

- **सामान्य कृषि नीति (CAP):** कृषि [युरोपीय संघ \(EU\)](#) का एकमात्र क्षेत्र है जसिकी एक सामान्य नीति है, CAP, जो कसिनों को सब्सिडी, प्रत्यक्ष भुगतान, आपूर्ति नियंत्रण और समग्र समर्थन प्रदान करती है ।
- **ग्रोइंग फॉरवर्ड 2 (GF2):** यह कनाडा के कृषि और कृषि-खाद्य क्षेत्र के लयि पाँच वर्षीय संघीय-प्रांतीय-क्षेत्रीय नीतगित ढाँचा है । यह नवाचार, प्रतस्पर्द्धात्मकता और बाज़ार वकिस पर केंद्रति है ।

मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म (SADF)

- SADF फार्म भारतीय मानकों के अनुरूप वभिनिन कृषि पद्धतयिों और नवीन प्रौद्योगिकियिों के परीक्षण और कार्यानवयन के लयि प्रयोगात्मक स्थल के रूप में कार्य करेंगे ।
- ये फार्म वसितार अधिकारयिों, कृषकों और औद्योगिकि पेशेवरों को मानकीकृत कृषि पद्धतयिों के बारे में जानने के लयि एक मंच प्रदान करेंगे, जसि BIS द्वारा वत्तितीय सहायता प्रदान की जाएगी ।

भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता क्या है?

- NBC एक आदर्श संहिता है, जो भवन नरिमाण में शामिल सभी अभकिरणों के लयि व्यापक दशिनरिदेश प्रदान करती है ।
- इसे सर्वप्रथम वर्ष 1970 में प्रकाशति कयिा गया, वर्ष 1983 में संशोधति कयिा गया तथा वर्ष 2005 में संशोधति कयिा गया । वर्तमान संस्करण, **NBC वर्ष 2016, भवन नरिमाण के परिवर्तित परिदृश्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत कयिा गया था ।**
- **NBC 2016 के प्रमुख प्रावधान:** प्रभावी परयोजना नषिपादन हेतु पेशेवरों की भागीदारी पर बल देते हैं और एक सुव्यवस्थति, **एकल-खडिकी अनुमोदन प्रक्रयिा की सुवधि देते हैं जो ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस** को बढ़ावा देने के साथ-साथ **डिजिटलीकरण को** बढ़ावा देता है ।
- **दवियांग वयक्तयिों की** सुवधि हेतु अनुकूलति आवश्यकताओं को संशोधति कयिा गया है । वशिष रूप से **जटलि इमारतों और ऊँची इमारतों के लयि** उन्नत अग्न और जीवन सुरक्षा उपाय शामिल कयि गए हैं ।
- यह संहिता आपदाओं से सुरक्षा के लयि आधुनिक संरचनात्मक मानकों को शामिल करती है तथा नरिमाण में स्थरिता को बढ़ावा देने के लयि नवीन

सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।

भारत की राष्ट्रीय वदियुत संहिता (NEC) या नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड क्या है?

- NEC **BIS** द्वारा गठित एक सर्व-समावेशी **वदियुत स्थापना संहिता** है, जो संपूर्ण देश में वदियुत स्थापना संबंधी प्रथाओं को वनियमति करने के लिये दशानरिदेश प्रदान करती है।
 - NEC को मूलतः वर्ष 1985 में तैयार किया गया था तथा समकालीन अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप इसे वर्ष 2011 और 2023 में संशोधित किया गया था।
- **NEC 2023 के मुख्य प्रावधान:** वदियुत के झटके, आग और ओवरकरंट के वरिद्ध सुरक्षात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। **येआपात स्थितियों के लिये स्टैंडबाय पॉवर स्रोतों के डज़िाइन, चयन और रखरखाव को संबोधित करते हैं।**
- ये दशानरिदेश कृषि परविश में वदियुतीय खराबी के वरिद्ध सुरक्षा सुनिश्चिा करते हैं तथा **जल और संक्षारक पदार्थों जैसे बाह्य कारकों को ध्यान में रखते हैं।**
- इसके अतरिकित, ये संकटयुक्त परविश की संभावना के आधार पर खतरनाक क्षेत्नों को वर्गीकृत करते हैं और उनके अनुरूप दशानरिदेश प्रदान करते हैं, साथ ही सुरक्षा और गुणवत्ता पर बल देते हुए **सौर प्रतषिठानों के लिये व्यापक मानक भी प्रसतुत करते हैं।**

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

- BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जिसकी स्थापना BIS वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन जैसी गतविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिये बी.आई.एस. अधनियम 2016 के तहत स्थापति की गई है। **BIS का मुख्यालय नई दलिली में स्थति है।**
- BIS सुरक्षति एवं वशि्वसनीय गुणवत्ता वाली वस्तुएँ उपलब्ध कराता है, स्वास्थय संबंधी खतरों को न्यूनतम करता है, नरियात और आयात संबंधी वकिलप को बढ़ावा देता है, तथा मानकीकरण, प्रमाणन और परीक्षण के माध्यम से कसिमों के प्रसार को नरियंत्रित करता है।
- यह गुणवत्ता आश्वासन पर क्षमता नरिमाण कार्यक्रम आयोजित करता है और **अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) और अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रो-तकनीकी आयोग (IEC) में भारत का प्रतनिधित्व करता है।**
 - IEC एक अंतरराष्ट्रीय मानक नरिधारण निकाय है, जो सभी वदियुत, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिये अंतरराष्ट्रीय मानक प्रकाशति करता है।
 - **मानकीकरण प्रबंधन बोर्ड (SMB)** IEC का एक शीर्ष प्रशासनिक निकाय है, जो तकनीकी नीतगित मामलों के लिये ज़रिमदार है।

नषिकर्ष

प्रस्तावति NAC भारत में कृषि पद्धतियों के आधुनकीकरण की दशिा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। जैसे-जैसे विकास प्रकर्या आगे बढ़ेगी, भारत के कृषि परदिश्य की वविधि आवश्यकताओं की पूर्त करने वाली संहति को आकार देने में हतिधारकों की भागीदारी महत्त्वपूर्ण होगी।

?????? ???? ???? ???? ????:

प्रश्न: भारत में कृषि पद्धतियों के परविरतन में राष्ट्रीय कृषि संहति के उद्देश्यों और महत्त्व पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????:

प्रश्न: भारतीय कृषि की प्रकृति की अनश्चितताओं पर नरिभरता के मददेनज़र, फसल बीमा की आवश्यकता की वविचना कीजिये और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की मुख्य वशिषताओं का उल्लेख कीजिये। (2016)